दूसरे समीक्षा अध्ययन दल की स्थापना की गई थी। समीक्षा अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/तालुकों को अधिसूचित करने के लिए सरकार के विचाराधीन है।

Economic assistance for industrial development

2341. SHRI RAM NATH KOVIND: DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to provide special economic assistance to some States and Union Territories for industrial development of some districts of such States and Union Territories;

(b) if so, details thereof;

(c) whether Government have taken any action on these requests;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) At present an exercise to identify backward areas is on hand in the Ministry of Finance.

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय नवीकरण कोष

2342. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय नवीकरण कोष में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में निष्पादित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत आबंटित राशि का उन कार्यक्रमों के साथ ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) 1995-96 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत भुगतान करने और श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नियुक्ति कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के उपक्रम सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 209.58 करोड़ रुपये (अनअंकेक्षित अनंतिम) की राशि वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को परामर्श देने, पुनःप्रशिक्षित करने और पुनर्नियुक्ति योजनाओं जिनमें आंध्र प्रदेश की योजनाएं भी शामिल है, पर 7.42 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

वर्ष 1995-96 में, ऊपर उल्लिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 300.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष से आबंटन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कर्मचारी सहायता केंद्रों आदि के लिए किया जाता है और यह आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को सहायता

2343. **श्री राघवजी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के बंद/रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दिया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना फरवरी 1992 में की है ताकि भारतीय उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान किया जा सके। तथापि, राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता फिलहाल केवल केन्द्र के सार्वजनिक उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और युक्तियुक्त श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति संबंधी योजनाओं तक ही सीमित है।

Census of SSIs

2344. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) when was the last census of small scale industries in the country was held and when new census would be completed;